भारत संघ .....अपीलार्थी

बनाम

आर. भूसल ...प्रतिवादी

(12 जुलाई, 2006)

(न्यायाधिपति अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति एस. एच. कपाडिया)

सेवा कानूनः सशस्त्र बल- वायु सेना- स्थायी आयोग के लिए दावा- अधिकारी अल्पकालिक सेवा आयोग प्रदान किया गया- हेलीकॉप्टर अल्पकालिक सेवा आयोग पाठ्यक्रम के साथ- प्रारंभिक अवधि के पूरा होने के बाद विचार किया गया लेकिन स्थायी आयोग के लिए अनुशंसित नहीं किया गया और रिहाई आदेश जारी किया गया क्योंकि उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन न्यूनतम आवश्यकता से कम था- चिकित्सा योग्यता भी आवश्यक श्रेणी से कम थी-आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उन्हें स्थायी आयोग से वंचित करने के लिए निम्न चिकित्सा डी श्रेणी को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए था- उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति दी-आयोजित, उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निष्कर्ष दलीलों से

परे थे-विभाग का विशिष्ट रुख लागू नीति विनियमों के तहत निर्धारित प्रदर्शन मानदंड था जिसे अधिकारी द्वारा पूरा नहीं किया गया था- चीजों की योग्यता में मानदंड या नीति विनियमों की प्रयोज्यता के संबंध में कोई विशिष्ट चुनौती नहीं है, उच्च न्यायालय को मामले की फिर से सुनवाई करनी चाहिए।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 1622/2004

(नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 18.2.2003 से, रिट याचिका संख्या 8307/2002 में।)

मोहम्मद युसुफ, किरण भारद्वाज और सुषमा सूरी. अपीलर्थी के लिए

एन एम कृष्णमणि, नरेंदर कौशिक, पंकज कौशिक और अशोक कुमार शर्मा- प्रतिवादी के लिए

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था :

न्यायाधिपति अरिजीत पासायत

भारत संघ ने प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिये विवादित निर्णय की वैधता पर सवाल उठाया है आक्षेपित निर्णय द्वारा ,उच्च न्यायालय ने वर्तमान

वर्तमान अपीलार्थी को रिट याचिकाकर्ता को स्थायी अनुमति देने का निर्देश दिया। आगे यह निर्देश दिया गया कि उनकी चिकित्सा योग्यता को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक रोजगार दिया जाए।

संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः

प्रत्यर्थी को संख्या 3 के साथ अल्पकालिक सेवा आयोग प्रदान किया गया था हेलीकॉप्टर शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स 19.2.1993. उनका प्रारंभिक कार्यकाल फरवरी 2001 में सेवा की शर्तों के अनुसार दस साल के लिए था, उन्हें स्थायी कमीशन देने पर विचार किया गया उपयुक्तता मूल्यांकन में न्यूनतम प्रदर्शित प्रदर्शन और चिकित्सा फिटनेस शामिल थी। पूर्व को पिछले तीन वर्षों के लिए गोपनीय वार्षिक रिपोर्ट में ग्रेडिंग से और अनिवार्य गुणों के आधार पर शामिल किया जाना था जैसे व्यावसायिक ज्ञान, नौकरी प्रवीणता अखंडता, वफादारी, निर्भरता, भावना जिम्मेदारी, साहस (मानसिक और शारीरिक), वहन और स्थायी कमीशन का अनुदान, पिछले तीन वर्षों के मूल्यांकन में न्यूनतम औसत 6.5 और चिकित्सा वर्गीकरण के संबंध में मानक में 6 से कम नहीं, अपीलार्थी के अनुसार आवश्यकता में चिकित्सा श्रेणी का वर्गीकरण ए-2-जी-2. की रेटिंग से कम नहीं थी, चिकित्सा स्वास्थ्य के संबंध में 6.5 की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले औसतन 6.0 है , वह ए 4 जी 3 की श्रेणी में था तदनुसार उसे बोर्ड द्वारा स्थायी कमीशन के लिए सिफारिश नहीं की गई थी और रिहाई

का आदेश 11.4.2002.को जारी किया गया था। प्रतिवादी के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी उनका मूल रुख यह था कि वह निचली चिकित्सा श्रेणी में था क्योंकि वह एक विमान दुर्घटना में शामिल था और इसे स्थायी कमीशन से इनकार करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए था, विशेष रूप से जब वायु सेना प्रमुख ने जांच में पाया कि किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता था और याचिकाकर्ता को लगी चोटों के लिए सेवा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था।

वर्तमान अपीलार्थी का रुख यह था कि कम चिकित्सा वर्गीकरण का स्थायी कमीशन से इनकार करने के निर्णय पर कोई असर नहीं था, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि रिट याचिकाकर्ता न्यूनतम प्रदर्शन मानदंडों को पूरा नहीं करता था।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने मामले को अपने उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं माना और इस तथ्य को देखने पर रिट याचिका की अनुमति दी कि इसके आधार पर अपनाए गए प्रदर्शन मानदंड और निर्धारण को कोई चुनौती नहीं थी।

प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया ।

हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका पर उच्च न्यायालय का विचार और निष्कर्ष कुछ सामग्रियों और कथित रियायत पर कार्यवाही करने से परे थे, यह जांच किए बिना कि क्या वह रियायत अच्छी तरह से स्थापित थी और क्या अपीलकर्ता को विनियमों की प्रयोज्यता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिला, जो उच्च न्यायालय के अनुसार रिट याचिका में मूल चुनौती थी कि अपीलकर्ता द्वारा पाई गई चिकित्सा की कमी ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया था। जवाबी हलफनामा में अपीलकर्ता -भारत संघ का विशिष्ट रुख यह था कि स्थायी कमीशन के लिए उपयुक्तता का आकलन करते समय चिकित्सा की कमी ही एकमात्र कारक थी। भारत संघ का विशिष्ट रुख यह था की लागू नीति विनियमन के तहत तय किए गए प्रदर्शन मानदंड प्रतिवादी द्वारा पूरे नहीं किए गए थे प्रत्युत्तर हलफनामे के क्षेत्र में मानदंड या नीति विनियमों की प्रयोज्यता के संबंध में कोई विशेष चुनौती नहीं थी।

इसलिए हम प्रतिवादी के विद्वान वकील की याचिका में कोई सार नहीं पाते हैं प्रत्यर्थी ने कहा कि हालांकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दलीलों से परे यात्रा की, लेकिन इसके निष्कर्ष कानून में उचित हैं।

उचित स्थिति में , उच्च न्यायालय को मामले की दोबारा सुनवाई करनी चाहिए। हमे यह स्पष्ट करना चाहिए कि हमने रिट में प्रतिवादी द्वारा उठाई गई याचिका की स्वीकार्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, इसलिए उच्च न्यायालय महसूस करता है कि वह पक्षों को अपने संबंधित वकील के संबंध में आगे की सामग्री रखने की अनुमति दे सकता है, जो अपीलकर्ता के लिए प्रस्तुत करता है कि अंतरिम आदेश के आधार पर प्रतिवादी सेवा में जारी है, जिसे देखते हुए, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह हमारे आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर रिट याचिका का निपटान करने की संभावना का पता लगाए।

अपील का तदनुसार निपटान किया जाता है । कोई लागत नहीं ।

आर. पी.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा